नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 160
दि. 09.10.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com


## प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सौंपा नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मेट्रो लाइन-3 का भी किया शुभारंभ

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। साथ ही, उन्होंने मुंबई मेट्रो लाइन-3 के अंतिम चरण को राष्ट्र को समर्पित किया और देश के पहले एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन का भी शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण और अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाओं के उद्घाटन से शहर की स्थिति एक वैश्विक विकास और अवसर केंद्र के रूप में और मजबूत होगी ह्व

शुरूआत में 2 करोड़ यात्रियों को मिलेगी सेवा

नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण पर 19,647 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और यह 1,160 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हवाई अड्डा सालाना 2 करोड़ यात्रियों और 5 लाख टन कार्गो को संभालने में सक्षम होगा। अंतिम चरण में, यह हवाई अड्डा 9 करोड़ यात्रियों और 32.5 लाख टन कार्गो की क्षमता वाला एक विश्व स्तरीय केंद्र बन जाएगा।

नवी मुंबई हवाई अड्डे से जुड़ी खास बातें:

1. भारत का पहला पूर्ण डिजिटल हवाई अड्डाः हवाई अड्डे पर वाहन पार्किंग स्लॉट पूर्व-बुकिंग, ऑनलाइन बैगेज ड्रॉप और इमिग्रेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, पूरी तरह से ऑटोमेटेड और अक-सक्षम टर्मिनल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा।

2. प्रारंभिक क्षमताः 1,160 हेक्टेयर में फैले हवाई अड्डे की शुरूआती स्थिति में एक रनवे और टर्मिनल के जरिए सालाना 2 करोड़ यात्री सेवा ले सकेंगे। पूरी क्षमता पर यह चार टर्मिनल और दो रनवे के जरिए सालाना 15.5 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा।

3. लागत और रोजगारः इस हवाई अड्डे का निर्माण ₹19,650 करोड़ में हुआ है। यहां से एविएशन, लॉजिस्टिक्स, आईटी, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है।

4. एयरलाइन योजनाएंः इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर जैसी कई एयरलाइंस ने पहले ही देश के विभिन्न शहरों के लिए फ्लाइट संचालन की योजना साझा कर दी है।

5. वाणिज्यिक संचालनः दिसंबर से वाणिज्यिक संचालन शुरू होगा, जिसमें 40% अंतरराष्ट्रीय यातायात होगा, जो धीरे-धीरे बढ़कर 75% तक पहुंच जाएगा।

## अयोध्या में बृहस्पति कुंड का लोकार्पण और संतों की प्रतिमा का हुआ अनावरण, सीएम-वित्तमंत्री रहे मौजूद

(जीएनएस)।

रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी। आज यहां केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेढ़ी बाजार चौराहे स्थित बृहस्पति कुंड का भव्य लोकार्पण किया साथ ही दोनों नेताओं ने दक्षिण भारतीय संतों की प्रतिमाओं का अनावरण किया।

लोकार्पण व अनावरण कार्यक्रम के बाद दक्षिण भारत से आये कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। सीएम योगी व वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जिन प्रतिमाओं का अनावरण किया उनमें संत श्री पुरंदर दास, श्री त्यागराज और श्री अरुणाचल कवि की प्रतिमा है।

रामनगरी अयोध्या आज फिर एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नगर में बने बृहस्पति कुंड का लोकार्पण करने के साथ ही परिसर में बनी दक्षिण भारत के संतों की प्रतिमाओं का अनावरण कर दिया।

बृहस्पति कुंड पर दक्षिण भारत के तीन प्रख्यात संतों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। जिनका अनावरण केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री ने किया है। बृहस्पति कुंड रामनगरी के 108 पौराणिक स्थलों में से एक है इस कुंड की महत्ता विभिन्न शास्त्रों में बताई गई है।

राम मंदिर परिसर के यात्री सुविधा केंद्र में एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इसमें अयोध्या की परंपरा, भक्ति और दक्षिण भारतीय संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिलेगा। इसको लेकर पुलिस-प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अयोध्या पहुंच गई हैं। इस मौके पर यूपी सरकार के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

## संक्षिप्त समाचार

### पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के आगमन पर स्वागत किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भारत की उनकी पहली ऐतिहासिक यात्रा के

आगमन पर हार्दिक स्वागत किया है। उनके साथ ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी आया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वह भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत और पारस्परिक रूप से समृद्ध भविष्य के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए कल होने वाली बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

## उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने संविधान सदन में भारत रत्न लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

(जीएनएस)।

उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज संविधान सदन में भारत रत्न लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की।

उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आपातकाल के दौरान भारत रत्न लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण ने अधिनायकवाद के विरुद्ध एक ऐतिहासिक जन आंदोलन का नेतृत्व किया और 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान किया, जिसने लाखों लोगों को लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने साझा किया कि उन्हें उन्नीस वर्ष की आयु में भारत रत्न लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आह्वान में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने पूरे जोश के साथ इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी तथा लोगों के सशक्तीकरण के एक प्रबल समर्थक के रूप में उभरे।

उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज दोपहर बाद उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में भारत रत्न लोक नायक श्री जय प्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित की।

### उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कामकाज और प्रमुख पहलों से अवगत कराया गया

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने आज संसद भवन में उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक के दौरान, उपराष्ट्रपति को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कामकाज और समाज के वंचित एवं हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाने में उसकी भूमिका से अवगत कराया गया।

## निफ्टम-के ने अपना छठा दीक्षांत समारोह और 13वां स्थापना दिवस मनाया, खाद्य उद्योगपतियों की अगली पीढ़ी को प्रोत्साहित किया

(जीएनएस)।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टम-के), कुंडली ने अपना 6ठा दीक्षांत समारोह और 13वां स्थापना दिवस भव्यता, शैक्षणिक गौरव और नवाचार की भावना के साथ मनाया।

दीक्षांत समारोह में केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री देवेश देवल और बीकानेरवाला के प्रबंध निदेशक श्री श्याम सुंदर अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। निफ्टेम-के के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) के अध्यक्ष प्रोफेसर वी. रामगोपाल राव ने समारोह की अध्यक्षता की।

दीक्षांत समारोह में कुल 262 विद्यार्थियों (126 बी.टेक, 92 एम.टेक, 27 एमबीए और 17 पीएचडी) को डिग्री प्रदान की गई जबकि सात मेधावी विद्यार्थियों को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किए गए।

समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रो. अजय कुमार सूद ने देश के खाद्य प्रसंस्करण परितंत्र को आकार देने में निफ्टेम-के की भूमिका की सराहना की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के युग में भी "भोजन सबसे बुनियादी मानवीय जरूरत बना हुआ है।" यह बताते हुए कि दुनिया भर में 2.6 अरब लोग स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकते, उन्होंने युवा प्रौद्योगिकीविदों से आग्रह किया कि वे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और करुणा का संयोजन करके सभी के लिए नवीन, पौष्टिक और किफायती खाद्य समाधान विकसित करें। उन्होंने यह भी कहा कि निफ्टेम को नवाचारों और गहन तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से देश में खाद्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है। उन्होंने संस्थान के लिए अनुसंधान के कुछ आगामी क्षेत्रों का भी सुझाव दिया।

### निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और सेवारत मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधानसभा के आम चुनाव और 6 राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के अनुसार, आयोग ने अधिसूचित किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

ऐसे मतदाता फॉर्म 12डी भरकर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर अपने बीएलओ के माध्यम से पीठासीन अधिकारी को जमा कर सकते हैं।

## केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित 'वीविंग इंडिया टूगेदर' राष्ट्रीय संगोष्ठी में बुनकरों और कारीगरों से बातचीत की

### केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय संगोष्ठी में पूर्वोत्तर के शिल्प कौशल की प्रशंसा की; आईसीएआर और सीएयू इम्फाल की ग्रामीण शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए सराहना की

(जीएनएस)।

केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित एनएएससी कॉम्प्लेक्स के सी. सुब्रमण्यम सभागार में आयोजित 'वीविंग इंडिया टूगेदर ' राष्ट्रीय संगोष्ठी में सहभागिता की और पूर्वोत्तर के बुनकरों, कारीगरों और प्रतिभागियों से संवाद किया।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर पूर्वोत्तर के कारीगरों और बुनकरों के समृद्ध शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा की।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने इस कार्यक्रम में बुनाई परंपराओं को बढ़ावा देने, कारीगरों को प्रशिक्षित करने और सामुदायिक शिल्प के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करने में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के प्रयासों की भी सराहना की।

इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और डेयर सचिव डॉ. मांगी लाल जाट और आईसीएआर के उपमहानिदेशक, कृषि विस्तार डॉ. राजबीर सिंह भी उपस्थित रहे।

इस कार्यक्रम ने कारीगरों को अपने अनुभवों, चुनौतियों और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया और नीति निमार्ताओं और अधिकारियों को पारंपरिक शिल्प कौशल और आधुनिक बाजारों के बीच तालमेल को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। इस संगोष्ठी ने ग्रामीण कारीगरों के समावेशी विकास के जरिए 'वोकल फॉर लोकल' और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को और भी रेखांकित किया।

## श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति – श्रम शक्ति नीति 2025' के मसौदे पर जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की

(जीएनएस)।

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति – श्रम शक्ति नीति 2025 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिया है। यह मसौदा नीति, विकासशील भारत @2047 की राष्ट्रीय आकांक्षा के अनुरूप एक निष्पक्ष समावेशी और भविष्योन्मुख कार्य-विश्व के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

श्रम धर्म-काम की गरिमा और नैतिक मूल्य की भारतीय सभ्यतागत भावना पर आधारित यह नीति एक ऐसे श्रम संस्कृति की परिकल्पना करती है जो प्रत्येक श्रमिक के लिए सुरक्षा, उत्पादकता और भागीदारी सुनिश्चित करे। इसका उद्देश्य एक संतुलित ढांचा तैयार करती है जो श्रमिकों के हितों को बढ़ावा देते हुए उद्यमों को विकसित होने और स्थायी आजीविका उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। श्रम शक्ति नीति 2025 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) को एक सक्रिय रोजगार सुविधा प्रदाता के रूप में स्थापित करेगी जो विश्वसनीय, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणालियों के माध्यम से श्रमिकों, नियोक्ताओं और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय को बढ़ावा देगा।

## चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने 93वें भारतीय वायु सेना दिवस पर शुभकामनाएं दीं

(जीएनएस)।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने भारतीय वायु सेना की 93 वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी वायु सेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों, नागरिकों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने वायुसेना की बार-बार यह साबित करने के लिए सराहना की कि कैसे वायु शक्ति रणनीतियों को आकार दे सकती है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जहां वायुसेना ने दुश्मन के इलाके में अंदर तक सटीकता से हमला करने की अपनी क्षमता की पुष्टि की।

सीडीएस ने दुश्मन के विमानों, हवाई हथियारों और ड्रोनों पर प्रभावी ढंग से नजर रखने और उन पर हमला करने के लिए भारतीय वायुसेना के सेंसर और रडार के जटिल नेटवर्क की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों द्वारा समर्थित भारतीय वायुसेना की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) और मानवरहित हवाई प्रणालियों (सीयूएएस) इकाइयों ने एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली (आईएसीसीएस) के तहत निर्बाध रूप से काम किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट परिणाम दिए। उन्होंने स्वदेशी प्लेटफार्मों को शामिल करने, उन्नत हथियार प्रणालियों को अपनाने और संपूर्ण एयरोस्पेस क्षेत्र में संचालन के लिए सिद्धांतों के विकास के माध्यम से आधुनिकीकरण की दिशा में भारतीय वायुसेना के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की।

जनरल अनिल चौहान ने युद्ध के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा, "युद्ध का स्वरूप एक गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और भविष्य के संघर्षों के तकनीक-आधारित, तीव्र और विविध क्षेत्रों में संघर्षपूर्ण होने की उम्मीद है। इन परिस्थितियों में आधुनिक युद्ध में वायु शक्ति ही प्रमुख कारक होगी।"

### सरकार ने छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा के लिए 'तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0' आरंभ किया

शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर, 9 अक्टूबर 2025 को "तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 (टीएफवाईसी 3.0)" आरंभ करेगा, जो पूरे भारत में तंबाकू मुक्त शिक्षण वातावरण बनाने और युवा नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति सरकार की वचनबद्धता की पुष्टि करता है। यह राष्ट्रीय अभियान तंबाकू मुक्त पीढ़ी के सरकार के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तंबाकू का सेवन एक बड़ी जन स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है, जिससे भारत में प्रति वर्ष 13 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण (जीवाईटीएस-2019) के अनुसार, 13-15 वर्ष की आयु के 8.4 प्रतिशत छात्र वर्तमान में तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं।

## राष्ट्रीय संचार अकादमी (एनसीए), दूरसंचार विभाग (डीओटी) और जीएसएमए ने दूरसंचार नीति, अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

**एनसीए, डीओटी और जीएसएमए ने दूरसंचार क्षेत्र में नीति विकास, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए रणनीतिक साझेदारी की**

(जीएनएस)।

दूरसंचार विभाग (डीओटी), राष्ट्रीय संचार अकादमी (एनसीए) और जीएसएम एसोसिएशन (जीएसएमए) ने आज नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 में माननीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और सचिव (दूरसंचार) डॉ. नीरज मित्तल की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

एमओयू पर औपचारिक रूप से जीएसएमए के महानिदेशक श्री विवेक बद्रीनाथ और एनसीए के महानिदेशक श्री अतुल सिन्हा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर जीएसएमए के मुख्य

नियामक अधिकारी (सीआरओ) श्री जॉन गिउस्टी और जीएसएमए के एपीएसी प्रमुख श्री जूलियन गोर्मन भी उपस्थित थे।

यह समझौता ज्ञापन दूरसंचार क्षेत्र में नीति विकास, अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में एनसीए और जीएसएमए के बीच सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करता है। इस सहयोग का उद्देश्य संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाकर, नियामक सर्वोत्तम प्रथाओं को आगे बढ़ाकर और स्थायी डिजिटल परिवर्तन के लिए अगली पीढ़ी की तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देकर भारत के डिजिटल इंडिया विजन को मजबूत करना है।

इस साझेदारी के अंतर्गत एनसीए और जीएसएमए मिलकर काम करेंगे:

डिजिटल समावेशन और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अनुसंधान, विश्लेषण और प्रशिक्षण पहल शुरू करना, डिजिटल विभाजन को पाटने, स्थिरता को बढ़ावा देने और एक डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के विकास का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करना।

## केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में प्रमुख स्टॉलों का दौरा किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज यशोभूमि, नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 के प्रदर्शनी क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत के डिजिटल परिवर्तन को सशक्त करने वाली प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का जीवंत प्रदर्शन देखा।

मंत्री महोदय ने अपने दौरे की शुरूआत दूरसंचार विभाग (डीओटी) मंडप के उद्घाटन से की, जहाँ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रमुख पहलों को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने 4जी और 5जी नेटवर्क के विस्तार, भारतनेट परियोजना की प्रगति, टेलीकॉम स्टार्टअप एक्सेलरेटर और स्वदेशी

दूरसंचार विनिर्माण एवं नवाचार को बढ़ावा देने वाली पहलों पर आधारित प्रदर्शनियों को देखा । मंत्री महोदय ने देश भर में किफायती कनेक्टिविटी, डिजिटल समावेशन और मजबूत दूरसंचार अवसंरचना को सक्षम बनाने में दूरसंचार विभाग के निरंतर प्रयासों की सराहना की। मंत्री महोदय ने डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और नागरिक सुरक्षा को बढ़ाने में दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल और ऐप की भूमिका की सराहना की।

सी-डॉट पैवेलियन में, मंत्री महोदय ने 4जी, 5जी और उपग्रह संचार के साथ-साथ प्रारंभिक चरण की 6जी तकनीकों में स्वदेशी रूप से विकसित समाधानों का प्रदर्शन करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ बातचीत की। उन्होंने भारत के आत्मनिर्भर डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने वाले अनुसंधान, नवाचार और सुरक्षित दूरसंचार समाधानों को आगे बढ़ाने में सी-डॉट की भूमिका की सराहना की।

## भारत नवाचार को प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाकर इसका लोकतंत्रीकरण कर रहा है : डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर

**प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन भारत को कनेक्टिविटी से लेकर वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की ओर ले जा रहा है कॉलेज छात्रावासों से लेकर अंतरिक्ष मिशनों तक भारत में नवाचार इंजन अब समावेशी हैं**

(जीएनएस)।

केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के अवसर पर "कनेक्टिविटी से आगे: भविष्य के नवाचार के इंजनों का लोकतंत्रीकरण" के विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत नवाचार को एक विशिष्ट प्रयास से जनांदोलन में बदल रहा है।

डॉ. चंद्रशेखर ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत एक ऐसा नवाचार इको-सिस्टम तैयार कर रहा है जो समावेशी, सुलभ और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी हो। उन्होंने कहा, "हम भविष्य के नवाचार के इंजनों को प्रत्येक भारतीय के लिए उपयोगी बनाकर इसका लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं।"

डॉ. चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय चिंतन में आए बदलाव को भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अटल टिंकरिंग लैब्स से लेकर स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत तक की पहल नवाचार को सभी के लिए सुलभ बना रही हैं। भारत की विरासत - शून्य और शतरंज - पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, "नवाचार हमारे डीएनए में है और हम इसे एक नई सदी के लिए जागृत कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "हमने जो हासिल किया है वह व्यवस्थित है।

## आत्मनिर्भर भारत के लिए सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई के प्रयोग से स्वदेशी कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार, वास्तव में असरदार प्रभाव दिखा रहे हैं: श्री एस. कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(जीएनएस)।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सचिव श्री एस. कृष्णन ने मवेशियों के स्वास्थ्य की निगरानी और दालों, चावल, सूखी लाल मिर्च की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी आधारित डेयरी समाधान के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) प्रबंधन सहित विभिन्न प्रयोगों के लिए सेंसर आधारित गंध निगरानी प्रणाली की शुरूआत की घोषणा की है।

एग्रीइनइक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें कृषि और पर्यावरण क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास, परिनियोजन, प्रदर्शन और व्यावसायीकरण शामिल है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन, उन्नत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), कोलकाता द्वारा नोडल एजेंसी

के रूप में किया जा रहा है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और उद्योगों की एजेंसियां भाग ले रही हैं। उपरोक्त सभी पाँच प्रौद्योगिकियों का विकास और परीक्षण इस कार्यक्रम के तहत किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव की मौजूदगी में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) और उत्पाद लॉन्च का विवरण इस प्रकार है:

सी-डैक (के), आईआईटी, खड़गपुर और आईसीएआर-एनडीआरआई, कल्याणी द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित डेयरी समाधान की प्रौद्योगिकी का मेसर्स हैंडहोल्डर्स ग्लोबल, भुवनेश्वर को हस्तांतरण: इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित डेयरी समाधान दो प्रौद्योगिकियों का एक पैकेज है, जिसमें मवेशी स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली (गो-पी) और मास्टिटिस डिटेक्शन (एमएएसटी-डी) शामिल हैं। गो-पी मवेशियों के लिए पहनने योग्य कॉलर-माउंटेड आईपी67 रेटेड डिवाइस है, जो कृत्रिम गभार्धान के लिए मवेशियों के 'तापमान' की स्थिति को भांपने के लिए वास्तविक समय में शारीरिक तापमान परिवर्तन की निगरानी करता है, जो मवेशी प्रजनकों के लिए एक प्रमुख जरुरत होती है।

## आईआईसीए ने 'जनजातीय विकास के लिए सीएसआर उत्कृष्टता का लाभ' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का समापन किया

**यह सम्मेलन समुदाय-केंद्रित सीएसआर पहलों के माध्यम से समावेशी, सहयोगात्मक और सतत विकास के आह्वान के साथ द्वितीय आईआईसीए सीएसआर दिवस का प्रतीक है**

**डीपीई सचिव श्री के. मोसेस चालई ने सीएसआर व्यय पर डीपीई दिशानिर्देशों पर प्रकाश डाला; स्पष्ट उद्देश्यों, मापनयोग य लक्ष्यों का आह्वान किया और ठोस सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए**

**एमसीए सचिव श्रीमती दीप्ति गौर मुखर्जी ने जनजातीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए नीति निमार्ताओं, उद्योगपतियों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं को एक साथ लाने वाले एक सहयोगी मंच के निर्माण के लिए आईआईसीए की सराहना की**

**कारपोरेट सामाजिक दायित्व को विभिन्न गतिविधियों को बढ़कर तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए - आईआईसीए के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह**

(जीएनएस)।

जनजातीय विकास के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) उत्कृष्टता का लाभ उठाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का समापन सत्र 7 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) द्वारा आयोजित किया गया था। इस **धन-आधारित मार्गदर्शन पर प्राथमिकता सुनिश्चित करते हुए वित्तीय योगदान से आगे**

## भारत ई-बैंक गारंटी के लिए वास्तविक समय डिजिटल दस्तावेज निष्पादन के साथ पेपरलेस शासन की ओर अग्रसर

**बैंक, एनबीएफसी, पूंजी बाजार संस्थाओं और कॉर्पोरेट संस्थाओं जैसे 60 से अधिक संस्थानों को लाभ क्योंकि बैंक गारंटी जारी करने, नवीनीकरण और इन्वोकेशन का काम वर्तमान कुछ दिनों की जगह कुछ मिनटों में किया जा सकता है**

**राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) के एंटिटी लॉकर को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के डिजिटल डॉक्यूमेंट निष्पादन प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करना ताकि त्वरित, पारदर्शी और कानूनी रूप से अनुपालन योग्य डिजिटल कार्यप्रवाह को बढ़ावा दिया जा सके**

**डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन और निष्पादन को बढ़ाने के लिए एनईजीडी और एनईएसएल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए; भारत के डिजिटल गवर्नेंस विजन में तेजी लाने और उद्यमों के लिए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य**

(जीएनएस)।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा विनियमित एक सूचना उपयोगिता केंद्र, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) ने व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं के लिए डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन को बढ़ाने और एकीकृत करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में एनईजीडी के निदेशक श्री जेएल गुप्ता और एनईएसएल के एमडी और सीईओ श्री देबज्योति रे चौधरी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस सहयोग के माध्यम से, एनईजीडी का क्लाउड-आधारित दस्तावेज प्रबंधन प्लेटफॉर्म, एंटिटी लॉकर झ जो दस्तावेज जारी करने, भंडारण, साझाकरण और सत्यापन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से डिजिलॉकर पहल का एक विस्तार है झ एनईएसएल के डिजिटल दस्तावेज निष्पादन (डीडीई) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत होगा। एनईएसएल का डीडीई प्लेटफॉर्म एक अग्रणी समाधान है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) सहित अनुबंधों के डिजिटल, कागज रहित और सुरक्षित निष्पादन की सुविधा प्रदान करता है, जो डिजिटल रूप में कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं।

यह समझौता ज्ञापन ई-बीजी के लाभार्थियों और आवेदकों को एनईएसएल के ई-बीजी रिपॉजिटरी से सीधे अपने संबंधित एंटिटी लॉकर खातों में डिजिटल रूप से निष्पादित बैंक गारंटी प्राप्त करने और उन तक सुरक्षित रूप से पहुंचने में सक्षम बनाता है। यह एकीकरण तेज, अधिक पारदर्शी और कानूनी रूप से अनुपालन योग्य डिजिटल कार्यप्रवाह को बढ़ावा देगा, जो भारत के त्वरित डिजिटल शासन और व्यापार सुगमता के विजन में सहायता करेगा। एनईएसएल के ई-बीजी के लाभों में शामिल हैं

## भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 10 अक्टूबर 2025 को "सुशासन और अभिलेख 2025" पर प्रदर्शनी लगाएगा

**प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे**

(जीएनएस)।

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) सुशासन माह के अनुसरण में 10 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में "सुशासन और अभिलेख 2025" नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत सुबह 10 अक्टूबर की सुबह 10:00 बजे करेंगे।

स्वच्छता और सुशासन एक समृद्ध समाज के अभिन्न अंग हैं, जो सार्वजनिक आचरण, सामाजिक अंत:क्रिया और कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को आकार देते हैं। इस संबंध में प्रमुख राष्ट्रीय पहलों में से एक स्वच्छ भारत अभियान रहा है, जिसने न केवल स्वच्छता और जन स्वास्थ्य में सुधार किया है, बल्कि राष्ट्र की अभिलेखीय विरासत के संरक्षण में भी योगदान दिया है। 2021 और 2025 के बीच, विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने एक व्यापक अभिलेख प्रबंधन अभियान चलाया, जिसमें 75,500 से अधिक ऐतिहासिक रूप से मूल्यवान दस्तावेजों की पहचान की गई और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में भेजा गया।

इस प्रदर्शनी में इन अभिलेखों के चयनित संग्रह को प्रदर्शित किया जाएगा जो सुशासन के स्तंभों के रूप में पारदर्शिता, जवाबदेही और अभिलेख-संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। यह प्रदर्शनी भारत के प्रशासनिक विकास और प्रभावी शासन में दस्तावेजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।

प्रदर्शनी का एक विशेष खंड श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी सरकार ने समावेशी विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया, और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जिनका विज्ञान, प्रौद्योगिकी और युवा सशक्तिकरण में योगदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, जैसे प्रख्यात नेताओं को श्रद्धांजलि होगा। इन आख्यानों के माध्यम से, यह प्रदर्शनी राष्ट्र की विकास गाथा को आकार देने में शासन और अभिलेखीय संरक्षण के बीच गतिशील संबंधों को रेखांकित करती है।

प्रदर्शनी में विभिन्न मंत्रालयों के बहुमूल्य अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे, जो भारत की शासन व्यवस्था और विकास की प्रगति को दर्शाते हैं:

राष्ट्रपति सचिवालय: मुख्य आकर्षणों में जनरल एस. एच. एफ. जे. मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत करने से संबंधित अभिलेख तथा प्रमुख औपचारिक दस्तावेज शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की शुरूआत और चुनाव सुधारों को प्रदर्शित किया जाएगा।

गृह मंत्रालय: विजय दिवस समारोह और पंचायती राज की उन्नति से संबंधित दस्तावेज।

विद्युत मंत्रालय: टिहरी बांध और सरदार सरोवर बांध जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्रदर्शनी में भाग लेने वाले अन्य मंत्रालय और विभाग - जिनमें संसदीय कार्य मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि तथा न्याय मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार शामिल हैं - रेलवे क्षेत्र में विधायी सुधार, व्यापार समझौते, जल संसाधन प्रबंधन, कानूनी विकास, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और तकनीकी नवाचार को दर्शाते हुए प्रमुख दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।

## केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने ग्लोबल बिग कैट्स फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2025 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए

**दूरदर्शी टाइगर@2047 योजना के अंतर्गत भारत अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक प्रत्येक संभावित टाइगर लैंडस्केप को सुरक्षित करने के लिए कार्य कर रहा है: श्री भूपेंद्र यादव**

**जन भागीदारी वन्यजीव संरक्षण की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है - लद्दाख में हिमाल रक्षक, मध्य प्रदेश में चीता मित्र और गुजरात में वन्य प्राणी मित्र, सामुदायिक प्रबन्धन की शक्ति के प्रतीक हैं: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री**

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट्स फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2025 के पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ऊजार्वान नेतृत्व में राष्ट्र ने न केवल अपने संरक्षण ढांचे को मजबूत किया है, बल्कि यह भी परिभाषित किया है कि विकास और प्रकृति कैसे सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।"

## दिल्ली में 'ब्रीदेबल आर्ट' का उद्घाटन किया गया - यह वायु शुद्धिकरण करने वाले पौधों और टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग करके बनाई गई एक अभिनव, जीवंत संरचना है, जो वायु गुणवत्ता और स्थिर जीवन से जुड़ी जागरूकता को बढ़ावा देती है

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की संयुक्त सचिव सुश्री नमिता प्रसाद ने आज रोहिणी स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में 'ब्रीथेबल आर्ट' का उद्घाटन किया। इस आर्ट की स्थापना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित की गई थी और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इसके लिए सहयोग प्रदान किया। यह पहल पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान एवं कौशल विकास (ईईएआरएसडी) योजना के पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण एवं आजीविका कार्यक्रम (ईआईएसीपी) के तहत आयोजित 'ब्रीथ ऑफ चेंज - स्वच्छ वायु, नीला आकाश' अभियान का एक हिस्सा है।

'ब्रीदेबल आर्ट' एक नवोन्मेषी, जीवंत संरचना है—जिसे वायु शुद्धिकरण करने वाले पौधों और टिकाऊ सामग्रियों से बनाया गया है—जो वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और टिकाऊ शहरी जीवन को बढ़ावा देने के लिए एक संवादमूलक जन-सहभागिता संस्थापन के रूप में काम करेगी। क्यूआर-कोड-सक्षम शैक्षिक सामग्री के माध्यम से, आगंतुक पौधों की शारीरिक विशेषताओं और वायु को शुद्ध करने में उनकी भूमिका के बारे में जान सकते हैं। 'ब्रीदेबल

आर्ट' एक अधिक हरित, अधिक सांस लेने योग्य दिल्ली के विजन का प्रतीक है, जहां कला और प्रकृति सह-अस्तित्व में हैं और प्रत्येक नागरिक को याद दिलाते हैं कि स्थिरता एक सांस से ही आरंभ होती है।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता की लगातार बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए, यह स्थापना एक प्राकृतिक समाधान प्रदान करती है और साथ ही शहरी हरित क्षेत्रों को भी समृद्ध बनाती है। इस संरचना की परिकल्पना:

छात्रों, इको-क्लबों और स्थानीय निवासियों के लिए एक शैक्षिक केंद्र के रूप में कार्य करने।

आरडब्लूए, स्कूल, कॉलेज, नगर निकाय और स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए एक सामुदायिक पहल के रूप में कार्य करने।

नागरिक निकायों और स्थानीय समूहों के सहयोग से दीर्घकालिक रखरखाव के साथ वायु प्रदूषण के हॉटस्पॉट में कार्यनीतिक युक्ति के रूप में की गई है।

इस स्थापना के अपेक्षित परिणामों में पर्यावरण जागरूकता में वृद्धि, पर्यावरण-अनुकूल जीवन शैली को व्यापक रूप से अपनाना तथा प्रकृति-आधारित समाधानों के माध्यम से शहरी स्थानों का रूपांतरण शामिल है - जिससे दिल्ली में स्वच्छ वायु जागरूकता के लिए एक प्रमुख मॉडल की स्थापना होगी।

'ब्रीथेबल आर्ट' में उपयोग में लाये गए वायु शुद्धिकरण पौधों में एरेका पाम, बैम्बू पाम, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, पारिजात, पीस लिली, एरोहेड, वीपिंग फिग और ज़िगजैग प्लांट शामिल हैं। ये प्रजातियां - खासकर शुष्क सर्दियों के महीनों में जब सांस लेने में कष्ट सामान्य बात होती है, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन जैसे सामान्य बाहरी प्रदूषकों को हटाने, आर्द्रता के स्तर को नियंत्रित करने और वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जानी जाती हैं।

'ब्रीदेबल आर्ट' प्रदर्शनी टिकाऊ शहरी जीवन और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक रचनात्मक और सार्थक कदम है। कला के सौंदर्यबोध को पौधों की प्राकृतिक वायु शुद्धिकरण क्षमता के साथ जोड़कर, यह सार्वजनिक स्थानों को पारिस्थितिक संतुलन के जीवंत प्रतीकों में बदल देती है। यह अभिनव पहल दर्शाती है कि कैसे प्रकृति-आधारित, सहभागी समाधान जागरूकता को प्रेरित कर सकते हैं, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं और स्वच्छ वायु तथा स्वस्थ शहरों के लिए व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

# सम्पादकीय

## नया खुलासा : सिंगर को जहर दिया?

मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत को लेकर रोज नए-नए खुलासे आ रहे हैं। बता दें कि जुबिन की मौत 19 सितम्बर, 2025 को सिंगापुर में हुई थी। बता दें कि जुबिन की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी। जुबिन, श्यामकानु महंत और उनकी कंपनी की ओर से ऑर्गेनाइज इवेंट के चौथे संस्करण में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर गए थे। सिंगापुर में जुबिन और उनके साथी स्कूबा डाइविंग के लिए गए थे। स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबिन ने पानी में छलांग मारी और कुछ ही क्षणों में तड़पते नजर आए। बताया गया है कि जुबिन गर्ग पानी में सांस लेने के लिए हाफ रहे थे और लगभग डूबने की स्थिति में थे, उस समय सिद्धार्थ शर्मा को जाबो दे, जाबो दे। (जाने दो जाने दो) चिल्लाते सुना गया। ऐसा एक गवाह ने कहा है। जुबिन की मौत के बाद इस मामले की जांच चल रही है। पेस्टिवल ऑर्गेनाइजर, सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और बैंड के दो मेंबर शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को गिरफ्तार कर 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हालांकि इस दौरान जुबिन के बैंड के मेम्बर शेखर ज्योति गोस्वामी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिसमें उन्होंने बताया कि सिंगापुर में जुबिन को जहर दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में पूछताछ के दौरान पुलिस के पास मौजूद ऑफिशियल डाक्यूमेंट में दी गई जानकारी के मुताबिक डिटेल्स ग्राउंड ऑफ अरेस्ट या रिमांड नोट में ज्योति ने आरोप लगाया कि जुबिन की सिंगापुर में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नार्थ ईस्ट इंडिया पेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्यामकानु महंत ने जहर दिया था। गवाह ने कहा कि जुबिन गर्ग एक ट्रेंड स्विमर थे यानी वह तैराकी में अपनी तह जानते थे और इसलिए डूबने से उनकी मौत नहीं हो सकती।

उसने आगे कहा गया है कि शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंत ने सिंगर को जहर दिया था और अपनी साजिश छिपाने के लिए जानबूझकर विदेश में जगह चुनी थी। सिद्धार्थ ने उन्हें नाव के वीडियो किसी के साथ शेयर न करने का भी निर्देश दिया था।

सीआईडी का 9 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) फिलहाल सिंगापुर में गर्ग की मौत से जुड़े मामले की जांच कर रहा है। सीआईडी के सूत्रों ने दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि की है। नोट में कहा गया है, गवाह शेखर ज्योति गोस्वामी के बयान से पता चला है कि जुबिन गर्ग की डेथ से पहले मौत का एक्सीडेंट दिखाने की साजिश रची गई थी। जुबिन के साथ सिंगापुर में रह रहे सिद्धार्थ शर्मा का आचरण संदिग्ध था जिसकी वजह से बीच समुद्र में खतरनाक तरीके से नाव डगमगाने लगी थी। साथ ही यह भी बताया गया कि डूबते वक्त जुबिन के मुंह से और नाक से झाग निकल रहा था तो सिद्धार्थ ने जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाए उसे एसिड रिफ्लक्स बताकर टाल दिया और दूसरों को आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं है। जुबिन की मौत की जांच के लिए असम सरकार ने मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का भी गठन किया है। राजनीतिक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सैकिया की अध्यक्षता वाला यह आयोग 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उधर जुबिन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने शनिवार को अपने पति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को लौटाते हुए कहा कि यह उनका निजी दस्तावेज नहीं है और जांचकर्ता ही बेहतर तय कर पाएंगे कि इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए या नहीं।

गरिमा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जांच में सिंगापुर में जुबिन की मौत के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगा लिया जाएगा। गरिमा ने कहा कि वह बस यही चाहती हैं कि जांच सही तरीके से की जाए और सच्चाई जल्द से जल्द सामने ने आए। जब गरिमा जुबिन के बैंड में शामिल शेखर ज्योति गोस्वामी के गायक को जहर दिए जाने के दावे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल किया कि वह (शेखर) इतने लंबे समय तक चुप क्यों रहे?

# श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जन विश्वास, सेवा और समर्पण के 24 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य में विकास सप्ताह के जश्न का दूसरा दिन

**डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और प्रधानमंत्री ने इस पूंजी को दीर्घकालिक समृद्धि के लिए देश की ताकत बनाने का संकल्प किया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल**

**मुख्यमंत्री की प्रेरक उपस्थिति में युवा, रोजगार और कौशल सशक्तिकरण समारोह संपन्न**

**658 भर्ती मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले 55 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र जबकि 25 हजार से अधिक युवाओं को प्रोविजनल ऑफर लेटर वितरित**

**उद्योगों के अनुरूप मानव संसाधन मुहैया कराने के लिए 100 से अधिक उद्योग साझेदारों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए**

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कौशल, इच्छा शक्ति और जोश के जरिए पत्थर से पानी निकालने की क्षमता रखने वाली युवा शक्ति को कौशल विकास की नई राह दिखाई
- युवाओं के नवाचार को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से अनेक स्टार्टअप आत्मनिर्भर बने और गुजरात स्टार्टअप रैंकिंग में लगातार 4 वर्षों से शीर्ष पर
- मुख्यमंत्री ने युवाओं से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी जैसे अभियानों को अपनाने का प्रेरक आह्वान किया

गांधीनगर, 08 अक्टूबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साफ कहा कि विशाल युवा शक्ति (डेमोग्राफिक डिविडेंड) हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस पूंजी को दीर्घकालिक समृद्धि के लिए देश की ताकत बनाने का संकल्प किया है।

उन्होंने यह बात राज्य में 7 से 15 अक्टूबर के दौरान मनाए जा रहे विकास सप्ताह के दूसरे दिन बुधवार को गांधीनगर में आयोजित युवा रोजगार और कौशल सशक्तिकरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। इस समारोह का राज्य के 33 जिलों के आईटीआई में सीधा प्रसारण किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गांधीनगर और विभिन्न मंत्रियों ने अलग-अलग जिलों में आयोजित समारोह में समग्र राज्य में आयोजित किए गए 658 भर्ती मेलों के दौरान निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने वाले 57,502 युवाओं को सांकेतिक तौर पर नियुक्ति पत्र भी वितरित किए।

राज्य सरकार के श्रम कौशल विभाग ने आईटीआई में ड्रॉपआउट की दर को कम करने के लिए प्रशिक्षुओं को प्रोविजनल ऑफर लेटर देने की पहल की है, इसके अंतर्गत 25,000 से अधिक युवाओं को यह लेटर वितरित किए।

इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और श्रम एवं रोजगार तथा उद्योग मंत्री श्री बळवंतसिंह राजपूत एवं महानुभावों की उपस्थिति में उद्योगों के अनुरूप मानव संसाधन बल मुहैया कराने के लिए 100 से अधिक उद्योग साझेदारों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने युवाओं को मिले इन रोजगार अवसरों को उनके घर-परिवार में दिवाली का आर्थिक उजियारा बनने के साथ-साथ



आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया कदम भी करार दिया।

उन्होंने कहा कि अपने कौशल, इच्छा शक्ति और जोश (स्किल, विल और जील) के जरिए पत्थर से भी पानी निकालने की क्षमता रखने वाली युवा शक्ति को प्रधानमंत्री ने कौशल विकास की एक नई राह दिखाई है। इन 24 वर्षों में गुजरात के युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर उन्हें 'जॉब सीकर' से 'जॉब गिवर' बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में 'हर हाथ को काम' का मंत्र साकार हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आने वाले उद्योगों को उचित मानवबल मुहैया कराने के लिए इंडस्ट्री और आईटीआई के बीच सहयोग का जो मॉडल प्रधानमंत्री ने दिया है, उसे कौशल पाठ्यक्रमों के जरिए आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने कौशल्य-द स्किल यूनिवर्सिटी शुरू की है।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के 12,000 से अधिक युवा ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), हेल्थ केयर और एग्रो सर्विसेज जैसे रोजगार के व्यापक अवसर वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में सफल हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात में युवा शक्ति के नवाचार को गति मिलने के कारण 12,500 से अधिक स्टार्टअप आत्मनिर्भर बने हैं और गुजरात लगातार 4 वर्षों से स्टार्टअप रैंकिंग में देश में अव्वल रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक में 15 मिलियन यानी डेढ़ करोड़ से अधिक युवाओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में गहन प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई है और कौशल एवं तकनीकी योग्यता के साथ जोड़ा है। ऐसे कुशल युवाओं को पीएम रोजगार अप्रेंटिसशिप के तहत उद्योगों में रोजगार भी दिए गए हैं। श्री पटेल ने इस मौके पर देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक लाख करोड़ रुपए की पीएम विकसित भारत रोजगार योजना पर भी प्रकाश डाला।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने युवा शक्ति से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल एवं हर घर स्वदेशी जैसे अभियानों को अपनाएं।

श्रम, कौशल एवं रोजगार मंत्री श्री बळवंतसिंह राजपूत ने कहा कि पूरे राज्य में मनाए जा रहे विकास सप्ताह के दौरान राज्य के 57 हजार से अधिक युवाओं को आज रोजगार पत्र वितरित किए गए हैं, जो हम सभी के लिए गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक अनूठी पहल की है, जिसके अंतर्गत रोजगार मेलों के साथ-साथ युवाओं को कंपनियों के मार्गदर्शन में पढ़ाई के तुरंत बाद नौकरी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

श्री राजपूत ने कहा कि आगामी समय में प्रवेश प्राप्त करने वाले 100 फीसदी युवाओं को पढ़ाई के दौरान ही स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। आज सिंगल विंडो के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के द्वारा नौकरी दी और हासिल की जा सकती है। रोजगार मेले एवं भर्तियों के अन्य माध्यमों से अनेक युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात की बेरोजगारी दर केवल 1.1 फीसदी है, जो देश की 3.2 फीसदी की तुलना में काफी कम है। सरकार इस दर में और कमी लाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

श्रम, कौशल एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि गुजरात सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि देश भर से नागरिक गुजरात में आकर अच्छी नौकरी प्राप्त कर यहां रह रह सकते हैं। उन्होंने रोजगार प्राप्त करने वाले सभी युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न उद्योगों को भी सहायता दी जाती है।

श्रम, कौशल और रोजगार विभाग के प्रधान सचिव श्री विनोद राव ने स्वागत भाषण में कहा कि आगामी समय में युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाले ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रभावी कार्य किया जाएगा। आज गांधीनगर सहित पूरे राज्य में युवाओं को नियुक्ति पत्र और प्रोविजनल ऑफर लेटर देने तथा उद्योगों के साथ एमओयू के करने के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगला वर्ष से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 100 फीसदी छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही प्रोविजनल ऑफर लेटर मिल जाएं।

रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशक श्री नितिन सांगवान ने आभार व्यक्त किया।

इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, गांधीनगर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिल्पाबेन पटेल, श्रम निदेशक श्री के.डी. लाखाणी, कौशल विकास निदेशक श्री कमलेश राठोड़ सहित श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में युवा एवं रोजगार दाता उपस्थित रहे। वहीं, पूरे राज्य से 1.5 लाख से अधिक युवा वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम से जुड़े।

# विकास सप्ताह : 9 अक्टूबर, पोषण दिवस: श्री नरेन्द्र मोदी के जनसेवा के 24 वर्षों के दौरान पोषण स्तर में सुधार के लिए कई योजना अमली की गई

**गुजरात की पोषण पहलों का बड़ा असर: 7 सालों में अंडरवेट बच्चे 39.7% से 17.2%, बौनेपन में 39% से 30.9%, शारीरिक दुर्बलता 25% से घटकर 6.7%**

- पोषण सुधा, दूध संजीवनी और पूर्णा योजना का बड़ा विस्तार, तीनों योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या 20 लाख के पार
- मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना 53,065 आंगनवाड़ी सेंटर्स में लागू, हर साल 5 लाख महिला-बच्चों तक लाभ पहुँचाने का लक्ष्य
- टेक होम राशन और हॉट कुक्ड मील से 28 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़े

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 8 अक्टूबर, 2025: भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसके 24 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी 24 वर्षों की जनसेवा की गाथा को उजागर करने के लिए, राज्य में 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। विकास सप्ताह के अंतर्गत, 9 अक्टूबर को पोषण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पिछले 24 वर्षों के दौरान, गुजरात में पोषण के स्तर में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं।

तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और उनके बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण और भोजन सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास किए। आज प्रधानमंत्री के रूप में उनके 'सही पोषण देश रोशन' के मंत्र को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात की पोषण संबंधी पहलों के सकारात्मक परिणाम धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पोषण संबंधी विभिन्न पहल अमली करने के कारण राज्य ने बच्चों के अंडरवेट, बौनेपन और शारीरिक दुर्बलता जैसी चुनौतियों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया है। पिछले 7 साल के आँकड़ों को देखें तो कद्दू यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेस के तहत पोषण को लेकर गुजरात सरकार के व्यापक और सघन प्रयासों के परिणामस्वरूप 2019 में अंडरवेट बच्चों का प्रतिशत 39.7% था, जो 2025 में घटकर 17.2% रह गया, बौनेपन 39% से 30.9% और शारीरिक दुर्बलता 25% से 6.7% तक कम हुई। यह उल्लेखनीय है कि राज्य की सभी पोषण संबंधी योजनाओं का लाभ लगभग 45 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है।

हर माँ, हर बच्चा पोषित: 5 लाख लाभार्थियों तक पहुँचने का मुख्यमंत्री मातृशक्ति मिशन

माताओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना राज्यभर में अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म के पहले दो साल तक महिलाओं और उनके बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। राज्य के 53,065 आंगनवाड़ी सेंटर्स में महिलाओं को प्रति माह 1 लीटर मूंगफली का तेल, 1 किलो तुअर दाल और 2 किलो चने की न्यूट्रीशन किट वितरित की जाती है।

इस पहल से न केवल माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है, बल्कि उनके समग्र विकास में भी मजबूती आई है। हर साल 5 लाख महिलाएँ और बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो ऐसा मिशन है, जो मातृत्व और बचपन के शुरुआती वर्षों में बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

टेक होम राशन और हॉट कुक्ड मील से 28 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़े

माताओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए गुजरात में 2017 से टेक होम राशन प्रोग्राम प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। राज्य के सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स तक राशन पहुंचाने का कार्य तीन प्रमुख डेयरी को-ऑपरेटिव्स और गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से किया जाता है। इस प्रोग्राम के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को हर महीने 1 किलो राशन के चार पैकेट उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं, छह महीने से तीन साल तक के सामान्य बच्चों को बाल शक्ति आहार के सात पैकेट और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को दस पैकेट दिया जाता है।

इसके साथ ही, 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में रोजाना हॉट कुक्ड मील भी प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चों का पोषण स्तर मजबूत होने के साथ उनके शुरुआती विकास में भी मदद मिलती है। अब तक टेक होम राशन प्रोग्राम से 16.5 लाख से अधिक माताएँ और बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि हॉट कुक्ड मील का लाभ 11.6 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंचा है। इस तरह से 28 लाख से अधिक लाभार्थी इन दोनों योजनाओं से जुड़ चुके हैं।

पोषण सुधा, दूध संजीवनी और पूर्णा: राज्य सरकार की मातृत्व और बाल स्वास्थ्य पहल

माताओं, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण को सशक्त बनाने के लिए गुजरात सरकार ने लगातार महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की हैं। पोषण सुधा योजना राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जिसकी शुरूआत 2017-18 में 10 जिलों से हुई थी और अब 14 आदिवासी जिलों के 106 ब्लॉकों में सक्रिय है। इस योजना के तहत हर महीने लगभग 1.2 लाख महिलाओं तक विशेष भोजन, आयरन और फॉलिक एसिड, कैल्शियम गोलियाँ और स्वास्थ्य परामर्श पहुंचाया जाता है।

इसी दिशा में दूध संजीवनी योजना ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसके तहत 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी में सप्ताह में पांच दिन 100 मिलीलीटर फोर्टीफाइड दूध दिया जाता है। वहीं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को हफ्ते में दो बार 200 मिलीलीटर पोषणयुक्त दूध उपलब्ध कराया जाता है। इस पहल से लगभग 9.3 लाख लाभार्थियों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है, जिससे माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य मजबूत हुआ है। इसी तरह, पूर्णा योजना के तहत राज्य की 15 से 18 साल की करीब 10 लाख किशोरियों को हर महीने 1 किलो के चार पैकेट पोषणयुक्त आहार और हर हफ्ते आयरन-फॉलिक एसिड टैबलेट्स उपलब्ध कराई जाती हैं। इन तीनों पहलों का उद्देश्य कुपोषण और एनीमिया को कम करने के साथ-साथ बच्चों और किशोरियों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना भी है।

# ई-नाम प्लेटफॉर्म का विस्तार: भारत के सबसे बड़े डिजिटल कृषि व्यापार प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए 9 नई वस्तुओं को जोड़ा गया

**ई-नाम प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं की संख्या बढ़कर 247 हो गई है, जिससे किसानों और व्यापारियों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं**

(जीएनएस)।

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 09 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करके राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के दायरे का विस्तार करके इसे और मजबूत किया है, जिससे इस मंच पर व्यापार योग्य कृषि वस्तुओं की कुल संख्या 247 हो गई है। यह महत्वपूर्ण कदम किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि व्यापक कमोडिटी कवरेज और बाजार एकीकरण को और मजबूत किया जा सके।

इस पहल का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उनके लिए अवसरों को बढ़ाना है, जो पूरे भारत के बाजारों को जोड़ता है।

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), जिसे ई-नाम पर व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदण्ड तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है, ने राज्य एजेंसियों, व्यापारियों, विषय विशेषज्ञों और एसएफएसी के साथ व्यापक परामर्श के बाद तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अनुमोदन से इन 09 नई वस्तुओं के लिए मापदण्ड विकसित किए हैं।

व्यापार योग्य मापदण्ड यह सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को उनकी उपज की वास्तविक गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्त हो, जिससे बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम हो और उनकी उनकी मोलभाव शक्ति मजबूत हो। यह पहल एक पारदर्शी व्यापारिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देती है, किसानों के हितों की रक्षा करती है, और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास में योगदान देती है।

अब तक डीएमआई ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कारोबार की जाने वाली 238 कृषि वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदंड तैयार किए हैं। 9 नई वस्तुओं के जुड़ने से यह संख्या बढ़कर 247 हो जाएगी, जिससे प्लेटफॉर्म की पहुंच और प्रभाव व्यापक हो जाएगा। जोड़ी गई 9 नई वस्तुएं हैं:

ग्रीन टी, चाय, अश्वगंधा की सूखी जड़ें, सरसों का तेल, लैवेंडर तेल, मेंथा ऑयल, वर्जिन जैतून का तेल, लैवेंडर के सूखे फूल, ब्रोकन राइस

व्यापार योग्य मापदण्ड वस्तुओं के लिए मानकीकृत ग्रेड या श्रेणियां प्रस्तुत करते हैं, जो कीमतों को सीधे गुणवत्ता से जोड़ते हैं और इस प्रकार किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करते हैं।

ई-नाम पोर्टल (इलेक्ट्रॉनिक) पर अब नए स्वीकृत व्यापार योग्य मापदंडों के उपलब्ध होने से यह प्लेटफॉर्म एक पारदर्शी, गुणवत्ता-संचालित बाजार के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करता है। यह पहल किसानों के लिए व्यापक बाजारों तक पहुँचने, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा सुनिश्चित गुणवत्ता मानकों से लाभ उठाने के द्वार खोलती है, जिससे अंततः उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि होती है।

यह कदम पारदर्शी डिजिटल उपकरणों के साथ किसानों को सशक्त बनाने, गुणवत्ता-संचालित व्यापार को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के भारत सरकार के संकल्प को रेखांकित करता है।

# एसईसीएल ने विशेष अभियान 5.0 के तहत 37 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र को स्वच्छ करने का लक्ष्य निर्धारित किया

**सीआईएल की सहायक कंपनी ने अपशिष्ट प्रबंधन, स्क्रैप निपटान और इलेक्ट्रॉनिक एवं वास्तविक फाइल समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया**

(जीएनएस)।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की मिनीरत्न सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने अपने प्रचालनगत और प्रशासनिक स्थानों पर स्वच्छता, दक्षता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना के साथ अपना महत्वाकांक्षी विशेष अभियान 5.0 आरंभ किया है।

अभियान के तहत, एसईसीएल ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैले 203 चिन्हित स्थलों पर 37,50,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस पहल का उद्देश्य कार्यालयों, खदानों और कॉलोनियों में स्थायी हाउसकीपिंग कार्यप्रणालियां सुनिश्चित करना तथा कार्यस्थल की स्वच्छता और सौंदर्य में सुधार करना है।

विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत प्रमुख लक्ष्य

लगभग 37.5 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले 203 स्थलों की सफाई और रखरखाव।

लगभग 3,000 मीट्रिक टन स्क्रैप सामग्री का सुरक्षित निपटान।

2,000 वास्तविक फाइलों और 6,500 ई-फाइलों की विस्तृत समीक्षा।

उचित सत्यापन के बाद 2,700 ई-फाइलें बंद कर दी गई।

कंपनी के भीतर रचनात्मकता

और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट से सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों का निर्माण।

यह अभियान प्रणालीगत फाइल समीक्षा और समापन के माध्यम से डिजिटल दस्तावेजीकरण कार्यप्रणालियों और कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन के एकीकरण पर भी जोर देता है, जो स्वच्छता और शासन में दक्षता के लिए भारत सरकार के व्यापक विजन के अनुरूप है।

पिछले वर्ष विशेष अभियान 4.0 के दौरान, एसईसीएल ने कई श्रेणियों में अपने लक्ष्यों को पार किया-सफाई स्थलों की संख्या, खाली की गई जगह और स्क्रैप निपटान के मामले में सभी कोयला सार्वजनिक उपक्रमों में कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया। कंपनी ने लोक-संपर्क और दृश्यता में भी अग्रणी स्थान अर्जित किया, कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों में सबसे अधिक ट्वीट और प्रेस विज्ञप्तियां दर्ज कीं, जिससे अभियान के क्रियान्वयन और संचार में राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक स्थापित हुआ।

# कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला नीलामी के अंतर्गत पांच कोयला ब्लॉकों के लिए स्वामित्व आदेश जारी किए

(जीएनएस)।

कोयला मंत्रालय ने अपने नामित प्राधिकरण के माध्यम से आज वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी के अंतर्गत 5 कोयला ब्लॉकों के लिए स्वामित्व आदेश जारी किए हैं। इन ब्लॉकों के लिए कोयला खदान विकास एवं उत्पादन समझौतों (सीएमडीपीए) पर 21 अगस्त, 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे।

जिन कोयला ब्लॉकों के लिए स्वामित्व आदेश जारी किए गए हैं, वे हैं टांडसी कक्क और टांडसी कक्क एक्सटेंशन, सेंदुरी, टुबेद के पश्चिम, चितरपुर (संशोधित), और फूटामुरा। इनमें से चार ब्लॉक आंशिक रूप से अन्वेषित हैं और एक ब्लॉक पूर्ण रूप से अन्वेषित है। इनकी अधिकतम निर्धारित क्षमता (ढ्ढक्र) लगभग 3.45 मिलियन टन प्रति वर्ष (टळढ्ढ) और लगभग 1,556.31 मिलियन टन (टळ) का भूगर्भीय भंडार है।

इन ब्लॉकों से लगभग ₹360 करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने

और लगभग ₹517 करोड़ का पूंजी निवेश आने की उम्मीद है। इसके अलावा, इनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4,664 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।

इन निहित आदेशों के जारी होने के साथ, अब कुल 125 कोयला ब्लॉक वाणिज्यिक कोयला नीलामी के अंतर्गत निहित या आवंटित हो चुके हैं। सामूहिक रूप से इन ब्लॉकों का कुल पीआरसी लगभग 265.844 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है जिससे लगभग ₹37,463 करोड़ का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 3,59,400 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

## राष्ट्रीय संचार अकादमी (एनसीए), दूरसंचार विभाग (डीओटी) और जीएसएमए ने दूरसंचार नीति, अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

**एनसीए, डीओटी और जीएसएमए ने दूरसंचार क्षेत्र में नीति विकास, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए रणनीतिक साझेदारी की**

(जीएनएस)।

दूरसंचार विभाग (डीओटी), राष्ट्रीय संचार अकादमी (एनसीए) और जीएसएम एसोसिएशन (जीएसएमए) ने आज नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 में माननीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और सचिव (दूरसंचार) डॉ. नीरज मित्तल की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

एमओयू पर औपचारिक रूप से जीएसएमए के महानिदेशक श्री विवेक बद्रीनाथ और एनसीए के महानिदेशक श्री अतुल सिन्हा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर जीएसएमए के मुख्य

नियामक अधिकारी (सीआरओ) श्री जॉन गिउस्टी और जीएसएमए के एपीएसी प्रमुख श्री जूलियन गोर्मन भी उपस्थित थे।

यह समझौता ज्ञापन दूरसंचार क्षेत्र में नीति विकास, अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में एनसीए और जीएसएमए के बीच सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करता है। इस सहयोग का उद्देश्य संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाकर, नियामक सर्वोत्तम प्रथाओं को आगे बढ़ाकर और स्थायी डिजिटल परिवर्तन के लिए अगली पीढ़ी की तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देकर भारत के डिजिटल इंडिया विजन को मजबूत करना है।

इस साझेदारी के अंतर्गत एनसीए और जीएसएमए मिलकर काम करेंगे:

डिजिटल समावेशन और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अनुसंधान, विश्लेषण और प्रशिक्षण पहल शुरू करना, डिजिटल विभाजन को पाटने, स्थिरता को बढ़ावा देने और एक डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के विकास का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करना।

## केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में प्रमुख स्टॉलों का दौरा किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज यशोभूमि, नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 के प्रदर्शनी क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत के डिजिटल परिवर्तन को सशक्त करने वाली प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का जीवंत प्रदर्शन देखा।

मंत्री महोदय ने अपने दौरे की शुरूआत दूरसंचार विभाग (डीओटी) मंडप के उद्घाटन से की, जहाँ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रमुख पहलों को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने 4जी और 5जी नेटवर्क के विस्तार, भारतनेट परियोजना की प्रगति, टेलीकॉम स्टार्टअप एक्सेलरेटर और स्वदेशी

दूरसंचार विनिर्माण एवं नवाचार को बढ़ावा देने वाली पहलों पर आधारित प्रदर्शनियों को देखा । मंत्री महोदय ने देश भर में किफायती कनेक्टिविटी, डिजिटल समावेशन और मजबूत दूरसंचार अवसंरचना को सक्षम बनाने में दूरसंचार विभाग के निरंतर प्रयासों की सराहना की। मंत्री महोदय ने डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और नागरिक सुरक्षा को बढ़ाने में दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल और ऐप की भूमिका की सराहना की।

सी-डॉट पैवेलियन में, मंत्री महोदय ने 4जी, 5जी और उपग्रह संचार के साथ-साथ प्रारंभिक चरण की 6जी तकनीकों में स्वदेशी रूप से विकसित समाधानों का प्रदर्शन करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ बातचीत की। उन्होंने भारत के आत्मनिर्भर डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने वाले अनुसंधान, नवाचार और सुरक्षित दूरसंचार समाधानों को आगे बढ़ाने में सी-डॉट की भूमिका की सराहना की।

## भारत नवाचार को प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाकर इसका लोकतंत्रीकरण कर रहा है : डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर

**प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन भारत को कनेक्टिविटी से लेकर वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की ओर ले जा रहा है कॉलेज छात्रावासों से लेकर अंतरिक्ष मिशनों तक भारत में नवाचार इंजन अब समावेशी हैं**

(जीएनएस)।

केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के अवसर पर "कनेक्टिविटी से आगे: भविष्य के नवाचार के इंजनों का लोकतंत्रीकरण" के विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत नवाचार को एक विशिष्ट प्रयास से

जनांदोलन में बदल रहा है।

डॉ. चंद्रशेखर ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत एक ऐसा नवाचार इको-सिस्टम तैयार कर रहा है जो समावेशी, सुलभ और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी हो। उन्होंने कहा, "हम भविष्य के नवाचार के इंजनों को प्रत्येक भारतीय के लिए उपयोगी बनाकर इसका लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं।"

डॉ. चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय चिंतन में आए बदलाव को भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अटल टिंकरिंग लैब्स से लेकर स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत तक की पहल नवाचार को सभी के लिए सुलभ बना रही हैं। भारत की विरासत - शून्य और शतरंज - पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, "नवाचार हमारे डीएनए में है और हम इसे एक नई सदी के लिए जागृत कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "हमने जो हासिल किया है वह व्यवस्थित है।

## आत्मनिर्भर भारत के लिए सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई के प्रयोग से स्वदेशी कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार, वास्तव में असरदार प्रभाव दिखा रहे हैं: श्री एस. कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(जीएनएस)।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सचिव श्री एस. कृष्णन ने मवेशियों के स्वास्थ्य की निगरानी और दालों, चावल, सूखी लाल मिर्च की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी आधारित डेयरी समाधान के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) प्रबंधन सहित विभिन्न प्रयोगों के लिए सेंसर आधारित गंध निगरानी प्रणाली की शुरूआत की घोषणा की है।

एग्रीइनइक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें कृषि और पर्यावरण क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास, परिनियोजन, प्रदर्शन और व्यावसायीकरण शामिल है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन, उन्नत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), कोलकाता द्वारा नोडल एजेंसी

के रूप में किया जा रहा है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और उद्योगों की एजेंसियां भाग ले रही हैं। उपरोक्त सभी पाँच प्रौद्योगिकियों का विकास और परीक्षण इस कार्यक्रम के तहत किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव की मौजूदगी में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) और उत्पाद लॉन्च का विवरण इस प्रकार है:

सी-डैक (के), आईआईटी, खड़गपुर और आईसीएआर-एनडीआरआई, कल्याणी द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित डेयरी समाधान की प्रौद्योगिकी का मेसर्स हैंडहोल्डर्स ग्लोबल, भुवनेश्वर को हस्तांतरण: इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित डेयरी समाधान दो प्रौद्योगिकियों का एक पैकेज है, जिसमें मवेशी स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली (गो-पी) और मास्टिटिस डिटेक्शन (एमएएसटी-डी) शामिल हैं। गो-पी मवेशियों के लिए पहनने योग्य कॉलर-माउंटेड आईपी67 रेटेड डिवाइस है, जो कृत्रिम गभार्धान के लिए मवेशियों के 'तापमान' की स्थिति को भांपने के लिए वास्तविक समय में शारीरिक तापमान परिवर्तन की निगरानी करता है, जो मवेशी प्रजनकों के लिए एक प्रमुख जरुरत होती है।

## आईआईसीए ने 'जनजातीय विकास के लिए सीएसआर उत्कृष्टता का लाभ' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का समापन किया

**यह सम्मेलन समुदाय-केंद्रित सीएसआर पहलों के माध्यम से समावेशी, सहयोगात्मक और सतत विकास के आह्वान के साथ द्वितीय आईआईसीए सीएसआर दिवस का प्रतीक है**

**डीपीई सचिव श्री के. मोसेस चालई ने सीएसआर व्यय पर डीपीई दिशानिर्देशों पर प्रकाश डाला; स्पष्ट उद्देश्यों, मापनयोग य लक्ष्यों का आह्वान किया और ठोस सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए**

**एमसीए सचिव श्रीमती दीप्ति गौर मुखर्जी ने जनजातीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए नीति निमार्ताओं, उद्योगपतियों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं को एक साथ**

**लाने वाले एक सहयोगी मंच के निर्माण के लिए आईआईसीए की सराहना की**

**कारपोरेट सामाजिक दायित्व को विभिन्न गतिविधियों को धन-आधारित मार्गदर्शन पर प्राथमिकता सुनिश्चित करते हुए वित्तीय योगदान से आगे बढ़कर तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए - आईआईसीए के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह**

(जीएनएस)।

जनजातीय विकास के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) उत्कृष्टता का लाभ उठाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का समापन सत्र 7 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) द्वारा आयोजित किया गया था। इस

## भारत ई-बैंक गारंटी के लिए वास्तविक समय डिजिटल दस्तावेज निष्पादन के साथ पेपरलेस शासन की ओर अग्रसर

**बैंक, एनबीएफसी, पूंजी बाजार संस्थाओं और कॉर्पोरेट संस्थाओं जैसे 60 से अधिक संस्थानों को लाभ क्योंकि बैंक गारंटी जारी करने, नवीनीकरण और इन्वोकेशन का काम वर्तमान कुछ दिनों की जगह कुछ मिनटों में किया जा सकता है**

**राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) के एंटिटी लॉकर को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के डिजिटल डॉक्यूमेंट निष्पादन प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करना ताकि त्वरित, पारदर्शी और कानूनी रूप से अनुपालन योग्य डिजिटल कार्यप्रवाह को बढ़ावा दिया जा सके**

**डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन और निष्पादन को बढ़ाने के लिए एनईजीडी और एनईएसएल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए; भारत के डिजिटल गवर्नेंस विजन में तेजी लाने और उद्यमों के लिए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य**

(जीएनएस)।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा विनियमित एक सूचना उपयोगिता केंद्र, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) ने व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं के लिए डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन को बढ़ाने और एकीकृत करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में एनईजीडी के निदेशक श्री जेएल गुप्ता और एनईएसएल के एमडी और सीईओ श्री देबज्योति रे चौधरी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस सहयोग के माध्यम से, एनईजीडी का क्लाउड-आधारित दस्तावेज प्रबंधन प्लेटफॉर्म, एंटिटी लॉकर झ जो दस्तावेज जारी करने, भंडारण, साझाकरण और सत्यापन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से डिजिलॉकर पहल का एक विस्तार है झ एनईएसएल के डिजिटल दस्तावेज निष्पादन (डीडीई) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत होगा। एनईएसएल का डीडीई प्लेटफॉर्म एक अग्रणी समाधान है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) सहित अनुबंधों के डिजिटल, कागज रहित और सुरक्षित निष्पादन की सुविधा प्रदान करता है, जो डिजिटल रूप में कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं।

यह समझौता ज्ञापन ई-बीजी के लाभार्थियों और आवेदकों को एनईएसएल के ई-बीजी रिपॉजिटरी से सीधे अपने संबंधित एंटिटी लॉकर खातों में डिजिटल रूप से निष्पादित बैंक गारंटी प्राप्त करने और उन तक सुरक्षित रूप से पहुंचने में सक्षम बनाता है। यह एकीकरण तेज, अधिक पारदर्शी और कानूनी रूप से अनुपालन योग्य डिजिटल कार्यप्रवाह को बढ़ावा देगा, जो भारत के त्वरित डिजिटल शासन और व्यापार सुगमता के विजन में सहायता करेगा। एनईएसएल के ई-बीजी के लाभों में शामिल हैं

## भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 10 अक्टूबर 2025 को "सुशासन और अभिलेख 2025" पर प्रदर्शनी लगाएगा

**प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे**

(जीएनएस)।

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) सुशासन माह के अनुसरण में 10 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में "सुशासन और अभिलेख 2025" नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत सुबह 10 अक्टूबर की सुबह 10:00 बजे करेंगे।

स्वच्छता और सुशासन एक समृद्ध समाज के अभिन्न अंग हैं, जो सार्वजनिक आचरण, सामाजिक अंतःक्रिया और कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को आकार देते हैं। इस संबंध में प्रमुख राष्ट्रीय पहलों में से एक स्वच्छ भारत अभियान रहा है, जिसने न केवल स्वच्छता और जन स्वास्थ्य में सुधार किया है, बल्कि राष्ट्र की अभिलेखीय विरासत के संरक्षण में भी योगदान दिया है। 2021 और 2025 के बीच, विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने एक व्यापक अभिलेख प्रबंधन अभियान चलाया, जिसमें 75,500 से अधिक ऐतिहासिक रूप से मूल्यवान दस्तावेजों की पहचान की गई और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में भेजा गया।

इस प्रदर्शनी में इन अभिलेखों के चयनित संग्रह को प्रदर्शित किया जाएगा जो सुशासन के स्तंभों के रूप में पारदर्शिता, जवाबदेही और अभिलेख-संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। यह प्रदर्शनी भारत के प्रशासनिक विकास और प्रभावी शासन में दस्तावेजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।

प्रदर्शनी का एक विशेष खंड श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी सरकार ने समावेशी विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया, और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जिनका विज्ञान, प्रौद्योगिकी और युवा सशक्तिकरण में योगदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, जैसे प्रख्यात नेताओं को श्रद्धांजलि होगा।

प्रदर्शनी राष्ट्र की विकास गाथा को आकार देने में शासन और अभिलेखीय संरक्षण के बीच गतिशील संबंधों को रेखांकित करती है।

प्रदर्शनी में विभिन्न मंत्रालयों के बहुमूल्य अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे, जो भारत की शासन व्यवस्था और विकास की प्रगति को दर्शाते हैं:

राष्ट्रपति सचिवालय: मुख्य आकर्षणों में जनरल एस. एच. एफ. जे. मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत करने से संबंधित अभिलेख तथा प्रमुख औपचारिक दस्तावेज शामिल हैं।

भारत निर्वाचन आयोग: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की शुरूआत और चुनाव सुधारों को प्रदर्शित किया जाएगा।

गृह मंत्रालय: विजय दिवस समारोह और पंचायती राज की उन्नति से संबंधित दस्तावेज।

विद्युत मंत्रालय: टिहरी बांध और सरदार सरोवर बांध जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्रदर्शनी में भाग लेने वाले अन्य मंत्रालय और विभाग - जिनमें संसदीय कार्य मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि तथा न्याय मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय

इन आख्यानों के माध्यम से, यह

## दिल्ली में 'ब्रीदेबल आर्ट' का उद्घाटन किया गया - यह वायु शुद्धिकरण करने वाले पौधों और टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग करके बनाई गई एक अभिनव, जीवंत संरचना है, जो वायु गुणवत्ता और स्थिर जीवन से जुड़ी जागरूकता को बढ़ावा देती है

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की संयुक्त सचिव सुश्री नमिता प्रसाद ने आज रोहिणी स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में 'ब्रीथेबल आर्ट' का उद्घाटन किया। इस आर्ट की स्थापना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित की गई थी और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इसके लिए सहयोग प्रदान किया। यह पहल पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान एवं कौशल विकास (ईईएआरएसडी) योजना के पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण एवं आजीविका कार्यक्रम (ईआईएसीपी) के तहत आयोजित 'ब्रीथ ऑफ चेंज - स्वच्छ वायु, नीला आकाश' अभियान का एक हिस्सा है।

'ब्रीदेबल आर्ट' एक नवोन्मेषी, जीवंत संरचना है—जिसे वायु शुद्धिकरण करने वाले पौधों और टिकाऊ सामग्रियों से बनाया गया है—जो वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और टिकाऊ शहरी जीवन को बढ़ावा देने के लिए एक संवादमूलक जन-सहभागिता संस्थापन के रूप में काम करेगी। क्यूआर-कोड-सक्षम शैक्षिक सामग्री के माध्यम से, आगंतुक पौधों की शारीरिक विशेषताओं और वायु को शुद्ध करने में उनकी भूमिका के बारे में जान सकते हैं। 'ब्रीदेबल

आर्ट' एक अधिक हरित, अधिक सांस लेने योग्य दिल्ली के विजन का प्रतीक है, जहां कला और प्रकृति सह-अस्तित्व में हैं और प्रत्येक नागरिक को याद दिलाते हैं कि स्थिरता एक सांस से ही आरंभ होती है।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता की लगातार बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए, यह स्थापना एक प्राकृतिक समाधान प्रदान करती है और साथ ही शहरी हरित क्षेत्रों को भी समृद्ध बनाती है। इस संरचना की परिकल्पना:

छात्रों, इको-क्लबों और स्थानीय निवासियों के लिए एक शैक्षिक केंद्र के रूप में कार्य करने।

आरडब्लूए, स्कूल, कॉलेज, नगर निकाय और स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए एक सामुदायिक पहल के रूप में कार्य करने।

नागरिक निकायों और स्थानीय समूहों के सहयोग से दीर्घकालिक रखरखाव के साथ वायु प्रदूषण के हॉटस्पॉट में कार्यनीतिक युक्ति के रूप में की गई है।

इस स्थापना के अपेक्षित परिणामों में पर्यावरण जागरूकता में वृद्धि, पर्यावरण-अनुकूल जीवन शैली को व्यापक रूप से अपनाना तथा प्रकृति-आधारित समाधानों के माध्यम से शहरी स्थानों का रूपांतरण शामिल है - जिससे दिल्ली में स्वच्छ वायु जागरूकता के लिए एक प्रमुख मॉडल की स्थापना होगी।

'ब्रीथेबल आर्ट' में उपयोग में लाये गए वायु शुद्धिकरण पौधों में एरेका पाम, बैम्बू पाम, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, पारिजात, पीस लिली, एरोहेड, वीपिंग फिग और ज़िगजैग प्लांट शामिल हैं। ये प्रजातियां - खासकर शुष्क सर्दियों के महीनों में जब सांस लेने में कष्ट सामान्य बात होती है, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन जैसे सामान्य बाहरी प्रदूषकों को हटाने, आर्द्रता के स्तर को नियंत्रित करने और वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जानी जाती हैं।

'ब्रीदेबल आर्ट' प्रदर्शनी टिकाऊ शहरी जीवन और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक रचनात्मक और सार्थक कदम है। कला के सौंदर्यबोध को पौधों की प्राकृतिक वायु शुद्धिकरण क्षमता के साथ जोड़कर, यह सार्वजनिक स्थानों को पारिस्थितिक संतुलन के जीवंत प्रतीकों में बदल देती है। यह अभिनव पहल दर्शाती है कि कैसे प्रकृति-आधारित, सहभागी समाधान जागरूकता को प्रेरित कर सकते हैं, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं और स्वच्छ वायु तथा स्वस्थ शहरों के लिए व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

## केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने ग्लोबल बिग कैट्स फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2025 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए

**दूरदर्शी टाइगर@2047 योजना के अंतर्गत भारत अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक प्रत्येक संभावित टाइगर लैंडस्केप को सुरक्षित करने के लिए कार्य कर रहा है: श्री भूपेंद्र यादव**

**जन भागीदारी वन्यजीव संरक्षण की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है - लद्दाख में हिमाल रक्षक, मध्य प्रदेश में चीता मित्र और गुजरात में वन्य प्राणी मित्र, सामुदायिक प्रबन्धन की शक्ति के प्रतीक हैं: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री**

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट्स फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2025 के पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ऊजार्वान नेतृत्व में राष्ट्र ने न केवल अपने संरक्षण ढांचे को मजबूत किया है, बल्कि यह भी परिभाषित किया है कि विकास और प्रकृति कैसे सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।"